दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, बुधवार 20 नवम्बर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 53

महत्वपूर्ण एवं खास

तेलंगाना में बेटा नहीं पैदा करने पर पति ने दिया तीन तलाक

हैदराबाद (आरएनएस)। तीन तलाक को गैर-कानूनी घोषित करने के बावजूद भी ऐसी वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। हैदराबाद से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसमें एक शख्स ने सिर्फ इसलिए अपनी बीवी को तीन तलाक दे दिया। क्योंकि उसने बेटे को जन्म नहीं दिया। इतना ही नहीं, तलाक तो दिया ही दिया ऊपर से दूसरी शादी भी कर ली। महिला ने अब अपने शौहर के खिलाफ केस दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की है। मेहराज बेगम नाम की महिला ने अपने शौहर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है, जिसमें उसने कहा है कि बेटे को जन्म नहीं दे पाने के कारण उसके शौहर ने उसे तीन तलाक दे दिया, जबकि यह कानूनन प्रतिबंधित है। इतना ही नहीं, उस शख्स ने किसी दूसरी महिला से निकाह भी कर लिया। अब मेहराज न्याय की आस लेकर पुलिस के पास पहुंची हैं। उन्होंने कहा, उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा और मेरे शौहर को उसके किए की सजा मिलेगी।

चीन में कोयला खदान विस्फोट में 15 लोगों की मौत

पेइचिंग। चीन के शांक्शी प्रांत में एक कोयला खदान में विस्फोट से कम से कम 15 लोगों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हो गए। शांक्शी कोयला खदान सुरक्षा प्रशासन ने बताया कि यह घटना सोमवार उस समय हुई जब 35 खनिक पिंग्याओ काउंटी क्षेत्र के कोयला खदान में काम कर रहे थे। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई। सरकारी समचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, '11 खनिक वहां से सुरक्षित निकलने में सफल रहे।' अभी तक की जांच में पता चल है कि खदान में करीब 35 मजदूर काम कर रहे थे जिस वक्त यह हादसा हुआ। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। फिलहाल पूरे इलाके को खाली करा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दक्षिण-पश्चिम चीन के चोंगछिंग शहर में इसी महीने कोयला खदान में ब्लास्ट हुआ था। इस ब्लास्ट में 30 मजदूरों की मौत हो गई और बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था।

आतंकवादी हमले में माली के 24 सैनिकों की मौत, 17 जिहादी मारे गए: सेना

बमाको । देश के पूर्वी हिस्से में सोमवार को हुई झड़पों में माली के 24 सैनिकों की मौत हो गई और 17 जिहादी लड़ाके भी मारे गए। पश्चिमी अफ्रीकी देश में सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सेना ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि पूर्वोत्तर के कस्बे तबनकोर्ट के नजदीक माली और नाइजर के बल संयुक्त अभियान चला रहे थे जब गश्ती दलों पर आतंकियों ने हमला किया। सेना के मुताबिक इस हमले में 24 की मौत हो गई और 29 घायल हो गए। इस दौरान 17 जिहादी भी मारे गए और कम से कम 100 संदिग्धों को पकड़ा गया है। वक्तव्य में कहा गया कैदी नाइजर के सैनिकों के कब्जे में हैं। फ्रांस, अफ्रीकी पड़ोसियों और अमेरिका की मदद से माली की सेना इस्लामिक उग्रवाद पर लगाम लगाने के लिए संघर्ष कर रही है।

इलाज के लिए एयर एंबुलेंस के जरिए लंदन रवाना हुए नवाज शरीफ

लाहौर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के प्रमुख पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अपने अनुज शहबाज शरीफ और निजी चिकित्सक अदनान खान के साथ मंगलवार को इलाज के लिए एयर एंबुलेंस से लंदन रवाना हुए। एयर एंबुलेंस सुबह पौने नौ बजे लाहौर हवाई अड्डे पहुंची। एयर एंबुलेंस कतर होते हुए लंदन पहुंचेगी जहां विभिन्न बीमारियों से पीड़ित शरीफ का इलाज होना है। नवाज के साथ पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज और डा. खान समेत कुल सात लोग एंबुलेंस से लंदन गए हैं। जियो न्यूज के मुताबिक इससे पहले पीएममएल-एन की प्रवक्ता मरियम औरंगजेब ने कहा कि चिकित्सकों ने आज सुबह भी मेडिकल जांच की। उन्होंने कहा, यदि नवाज 15 दिन पहले रवाना होते तो अबतक उनका इलाज भी शुरू हो गया होता।

सुरक्षित घर और सुरक्षित पड़ोस बनाने की आवश्यकता:स्मृति

» दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति जुबिन इरानी ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों को हिंसा और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए उनके घरों और पड़ोस में सुरक्षा सुनिश्चित करना तात्कालिक आवश्यकता है।

महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन इरानी आज नई दिल्ली में महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा फेसबुक द्वारा आयोजित दूसरे दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन में प्रमुख भाषण दे रही थीं। महिला और बाल विकास मंत्री ने एनसीआरबी के 2017 के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि महिलाओं के विरूद्ध दर्ज अपराध के तीन लाख मामलों में अपराधी पति और संबंधी थे। इसलिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा का विषय घर के

नजदीक होता है। उन्होंने बताया कि एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार 42 प्रतिशत पुरुष घरेलू हिंसा को उचित बताते हैं और 62 प्रतिशत महिलाएं घरेलू हिंसा का समर्थन करती हैं।

दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के आयोजन का उद्देश्य सुरक्षा के विषय को प्रमुखता से उठाना है जबकि व्यक्ति और समुदाय डिजिटल प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं। शिखर सम्मेलन में 125 सिविल सोसाइटी संगठन, महिला अधिकार समूह, बाल सुरक्षा विशेषज्ञ तथा शिक्षाविद लैंगिग समस्या तथा जनसंचार पर विचार कर रहे हैं। इस सम्मेलन में सुरक्षा व्यवहारकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या निरोधक संगठन, दिव्यांगजन अधिकार समूह भाग ले रहे हैं जिन्हें डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को चलाने तथा युवाओं के सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए टूल बनाने का अनुभव प्राप्त है।

महिला और बाल विकास मंत्री ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र में महिलाओं की आवश्यकताओं के लिए वन-स्टॉप सेंटर जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि देश में प्रत्येक महीने 10 वन-स्टॉप सेंटर खुल रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक प्रत्येक जिले में एक वन-स्टॉप सेंटर होगा। उन्होंने बताया कि भारत के प्रत्येक जिले में तस्करी विरोधी इकाइयां होंगी। पहली बाहर सरकार द्वारा यह पहल की गई है। उन्होंने बताया कि थानों तक महिलाओं और बच्चों की पहुंच को सहज बनाने के लिए देश के प्रत्येक थाने में महिला सहायता डेस्क स्थापित किया जा रहा है क्योंकि अपनी सुरक्षा और जीवन को खतरा मानते हुए महिलाएं जब कभी संकट से घिरी होती हैं वे पहले थाना पहुंचती हैं। उन्होंने बताया कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के सहयोग से साइबर अपराध पोर्टल लॉन्च किया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय इस पोर्टल को मजबूत बनाने में सहायता दे रहा है ताकि महिलाएं साइबर धमकी, ऑनलाइन शर्मनाक हरकतों तथा ऑनलाइन धमकियों की शिकायतें दर्ज करने में सक्षम हो सकें।

महिला और बाल विकास मंत्री ने बताया कि उनका मंत्रालय भारत में सभी यौन अपराधियों की डिजिटल सूची बना रहा है ताकि न्योक्ताओं को जब कभी जरूरत हो कर्मचारियों की पृष्ठभूमि जांच सकें।

उन्होंने डिजिटल प्लेटफार्मों से भाषायी और सांस्कृतिक पहलुओं को देखने और दिव्यांग महिलाओं और बच्चों के मामलें में विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया।

सुप्रीम कोर्ट में मराठा आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई जनवरी, 2020 तक टली

नईदिल्ली (आरएनएस)। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोगों को शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की कानूनी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. शीर्ष अदालत ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को नियुक्त किया था. अब मामले की सुनवाई जनवरी, 2020 में होगी.

बता दें कि आरक्षण के लिए मराठा समाज के संघर्ष के बाद देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और नौकरियों में 16 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था कर दी. फडणवीस सरकार के फैसले के खिलाफा बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. हाईकोर्ट ने आरक्षण की कानूनी वैधता को बरकरार रखा, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है.

हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका के मुताबिक, फडणवीस सरकार ने 16 फीसदी आरक्षण देकर संविधान पीठ की ओर से आरक्षण पर तय 50 फीसदी की सीमा का उल्लंघन किया है. साथ ही आरोप लगाया गया है कि राजनीतिक दबाव में सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून बनाया गया. एसईबीसी आरक्षण कानून मराठा समुदाय को शिक्षा में 12 और नौकरी में 13 प्रतिशत आरक्षण देता है. यह शीर्ष अदालत के इंदिरा साहनी मामले में दिए फैसले में तय की गई 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का उल्लंघन है.

आईआईटी, एनआईटी और आईआईईएसटी के निदेशकों का सम्मेलन संपन्न

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति भवन में आज शिबपुर के मंगलवार को आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसटी के निदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें आईआईटी के 23, तथा एनआईआईटी और आईईएसटी के 31 निदेशकों के अलावा केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव और एआईसीटीई के अध्यक्ष ने भी भाग लिया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि यह साल का एक ऐसा समय है जब राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों की वायु गुणवत्ता बेहद खराब हो चुकी है।. ' हम सब एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं रही। पिछली कुछ सदियों में हाइड्रोकार्बन ऊर्जा ने पूरी दुनिया का परिदृश्य बदल कर रख दिया है और अब यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। यह उन देशों के लिए एक तरह की दोहरी चुनौती है जो अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को गरीबी से बाहर निकालना चाहते हैं। हमें इस चुनौती से निबटने के विकल्प तलाशने होंगे।' कोविंद ने कहा कि कई वैज्ञानिकों और भविष्यवक्ताओं ने दुनिया का अंत होने (डूम्स डे) की बात कही है। हमारे शहरों में आज-कल धुंध और कम दृश्यता जैसी स्थितियों को देख कर यह डर सताने लगा है कि भविष्य के लिए कही यह बात कहीं अभी ही सच नहीं हो जाए।

डॉ. हर्षवर्धन ने औषधि उत्पादों तक पहुंच पर आधारित विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने मंगलवार को नई दिल्ली में औषधि उत्पादों तक पहुंच पर आधारित विश्व सम्मेलन का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि हमें बड़े पैमाने पर जन कल्याण के लिए ज्ञान को साझा करने में इस विश्व सम्मेलन का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें चर्चाओं को व्यावहारिकता में बदलने की एक सशक्त प्रणाली विकसित करनी चाहिए। इस अवसर पर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी

कुमार चौबे, बांग्लादेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जाहिद मलिक, भूटान की स्वास्थ्य मंत्री सुल्योनपो डिचेन वांग्मो, नेपाल के उप प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्री उपेन्द्र यादव तथा नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. वी.के. पॉल आदि भी उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में सभी नीतिगत निर्णयों एवं कार्यक्रमों में स्वास्थ्य के मुद्दे को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने कहा कि समतामूलक, किफायती स्वास्थ्य सुविधाओं तक आसान पहुंच कायम करना हमारे सभी प्रयासों के केन्द्र में है।

व्यापक स्वास्थ्य कवरेज के तहत विश्व भर में चिकित्सा उत्पादों के बारे में अनुभवों को साझा करने तथा पहुंच बढ़ाने में इस सम्मेलन को एक बहुमूल्य मंच बताते हुए, डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि इस सम्मेलन से किफायती एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उत्पादों के बारे में अभिनव चिंतन का मार्ग प्रशस्त होगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. टैड्रोस ऐडरेनॉम गैब्रेयेसस ने वीडियो संदेश के माध्यम से सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विश्व भर के लोगों के लिए चिकित्सा उत्पादों की किफायती उपलब्धता के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की वचनबद्धता दोहराई।

सड़क सुरक्षा उपायों से 2010-2018 के दौरान दुर्घटनाओं में कमी हुई

» सड़क परिहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की

नईदिल्ली (आरएनएस)। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने आज अपनी रिपोर्ट 'भारत में सड़क दुर्घटनाएं - 2018' जारी की है। यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के परिवहन अनुसंधान शाखा का वार्षिक प्रकाशन है, जिसमें राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की पुलिस से मिले आंकड़ों के आधार पर दुर्घटनाओं, इससे होने वाली मौतों एवं घायलों के बारे में वर्षवार विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018 के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में 0.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2017 में 4,64,910 के मुकाबले 4,67,044 सड़क दुर्घटनाएं हुई। इस अवधि के दौरान मृत्यु दर में भी लगभग 2.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 2017 में 1,47,913 के मुकाबले 2018 में 151471 लोग मारे गए थे। सड़क दुर्घटना में घायलों की संख्या में 2017 की तुलना में 2018 में 0.33 प्रतिशत की कमी आई। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2010 तक दुर्घटनाओं, मौतों और घायलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके बाद वर्ष दर वर्ष मामूली उतार-चढ़ाव के साथ वे कुछ हद तक स्थिर हो गए। इसके अलावा, 2010-2018 की अवधि में दुर्घटनाओं के साथ-साथ दुर्घटनाओं की वार्षिक वृद्धि दर में भारी गिरावट आई और ऑटोमोबाइल के विकास की अधिक दर के बावजूद, पिछले दशकों की तुलना में कम थी। राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसमें कुल सड़क नेटवर्क का 1.94 प्रतिशत शामिल है, कुल सड़क दुर्घटनाओं के 30.2 प्रतिशत और 2018 में 35.7 प्रतिशत मौतों का कारण है। राज्य के राजमार्गों में सड़क की लंबाई का 2.97 प्रतिशत हिस्सा 25.2 प्रतिशत दुर्घटनाओं और 26.8 प्रतिशत मृत्यु का कारण है।

अन्य सड़कें, जो कुल सड़कों का लगभग 95.1 प्रतिशत हैं, क्रमशः 45 प्रतिशत दुर्घटनाओं और 38 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार थीं। सड़क उपयोगकर्ता की श्रेणी के द्वारा दुर्घटना संबंधी मौतों के संदर्भ में, पैदल चलने वालों की संख्या 15 प्रतिशत थी, साइकिल चालकों की हिस्सेदारी 2.4 प्रतिशत थी और दोपहिया वाहनों की संख्या 36.5 प्रतिशत थी।

वेस्टबैंक में इजरायली बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का उलंघन नहीं : पोम्पियो

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने घोषणा की है कि अमेरिका सरकार अब वेस्ट बैंक में स्थित इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ नहीं मानेगी। यह एक ऐसा कदम है, जो भविष्य में इजरायल-फिलिस्तीनी शांति वार्ता की गति मंद कर सकता है। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, पोम्पियो ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह फैसला जमीनी वास्तविकता के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा, यह निष्कर्ष कि अब हम इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में गलत नहीं मानेंगे, अनोखे तथ्यों, इतिहास और वेस्ट बैंक में नागरिक बस्तियों की स्थापना रोकने से उत्पन्न परिस्थितियों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय कानूनी बहस में सभी पक्षों की बातों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद लिया गया है। पोम्पियो ने कहा कि यह इजरायल और फिलिस्तीनियों के लिए बातचीत के लिए है। मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेष समन्वयक निकोले म्लादेनोव ने पिछले महीने कहा था कि कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजरायल की बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध हैं और शांति के लिए एक महत्वपूर्ण बाधा बनी हुई हैं।

ग्लोबल ट्रेड एंड कस्टम्स जर्नल का विशेषांक लॉन्च किया गया

नईदिल्ली (आरएनएस)। ग्लोबल ट्रेड एंड कस्टम्स जर्नल का विशेषांक 15 नवम्बर को नई दिल्ली के इस्लामिक कल्चर्ल सेंटर में लॉन्च किया गया। विशेषांक का संपादन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट सेंटर के प्रमुख प्रोफेसर डॉ. जेम्सजे नेदुमपारा ने किया और इसे नीदरलैंड के वोसल्टर्स केलुवे ने प्रकाशित किया है। जर्नल लॉन्च किये जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में भारत : विषय और परिदृश्य विषय पर पैनल चर्चा प्रारंभ हुई।

वाणिज्य विभाग के अपर सचिव सुधांशु पांडे ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि व्यापार समझौते महत्वपूर्ण हैं क्योंकि निवेशक न केवल विदेशी बाजार को देखते हैं, बल्कि यह भी देखते हैं कि वस्तु और सेवा क्षेत्र में अधिक पहुंच और एकीकरण के लिए किस तरह निवेश आकर्षित किया जाए।

उन्होंने कहा कि व्यापार और निवेश नीतियों पर समग्र रूप से और अंतर-मंत्रालय खेमे की जगह एकीकृत रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

आईआरसीटीसी ने गोल्डन चैरियट ट्रेन चलाने केएसटीडीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। भरतीय रेल की पर्यटन इकाई 'भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम लिमिटेड' (आईआरसीटीसी) ने गोल्डन चैरियट ट्रेन के संचालन और प्रचार के लिए आज नयी दिल्ली में रेल राज्य मंत्री सुरेश सी अंगड़ी और कर्नाटक के पर्यटन मंत्री सी टी रवि की मौजूदगी में कर्नाटक राज्य पर्यटन निगम - केएसटीडीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव के अलावा बोर्ड के अन्य सदस्य तथा आईआरसीटीसी और केएसटीडीसी के अधिकारी भी मौजूद थे।

के एसटीडीसी जल्दी ही रेलगाड़ी का परिचालन आईआरसीटीसी को सौंपने जा रहा है। आईआरसीटीसी केरल के पर्यटन स्थलों के अनुरूप गोल्डन चैरियट ट्रेन के परिचालन समय और ठहराव वाले स्थानों में बदलाव करने जा रहा है। ट्रेन की समय सारिणी में यह बदलाव राज्य के इतिहास, संस्कृति, वन्य जीव और प्राकृतिक आकर्षणों के अनुरूप होगा। इसमें बांदीपुर, मैसूर, हालीबीड, चिकमंगलूर, हाम्पी, बीजापुर और गोवा जैसे पर्यटन

स्थलों को जोड़ने का प्रस्ताव भी है। आईआरसीटीसी रेलगाड़ी की आंतरिक साज-सज्जा में बदलाव करने के बाद मार्च 2020 से इसका परिचालन शुरु कर देगा।

इस अवसर पर बोलते हुए, रेल राज्य मंत्री ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण और देश में कम से कम पांच पर्यटन स्थलों को देखने जाने के देशवासियों के लिए उनके स्पष्ट आह्वान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंगड़ी ने आईआरसीटीसी और केएसडीटीसी को टिकटों की कीमतें प्रतिस्पर्धी रखने का निर्देश दिया ताकि आम लोग भी इस ट्रेन की सुविधा का लाभ उठा सकें।

अंगड़ी ने कहा कि यह ट्रेन दक्षिण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देगी। मंत्री ने इस परियोजना की सफलता की कामना की। इस अवसर पर कर्नाटक के पर्यटन मंत्री ने कहा कि कर्नाटक सरकार और केएसटीडीसी 2008 से ही गोल्डन चैरियट ट्रेन का संचालन और रखरखाव देख रही है। यह पूरे दक्षिण भारत की पहली और एकमात्र लक्जरी रेलगाड़ी है। उन्होंने कहा कि यह रेलगाड़ी इस क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति और धरोहरों का दर्शन कराती है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि आईआरसीटीसी और केएसटीडीसी के बीच आज हुआ समझौता दोनों के लिए लाभदायी होगा और इस साझेदारी से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।